International Journal of Education and Science Research
Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-7, Issue-5 October- 2020, P-ISSN 2348-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

औद्योगिक विकास हेतु प्रयासों की समीक्षा का मूल्यांकन (दमोह जनपद के संदर्भ में)

[1]Jyoti Bairagi, [2]Dr.Gulab Singh Parmar
[1]Research Scholar, [2]Supervisor
Career Point University
Kota, Rajasthan

सार

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान अवधि तक देश में औद्योगिक विकास की दर में तीव्र वृद्धि देखने में आई है। औद्योगिक संसाधनों के चतुर्मुखी विकास के दृष्टिकोण से औद्योगिक संसाधनों में सभी प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार ने मध्यम एवं वृहद् इकाईयों की स्थानपा की कल्पना करने के साथ–साथ नयी औद्योगिक नीति लागू करते समय लघु एवं अत्यन्त लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। इस कारण उस समय से लेकर अब तक की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों की प्रगति के लिए उत्पादों का आरक्षण किया गया और उस वर्ग की इकाईयों को ज्यादा मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार प्रदान कर सकती है तथा सकल उत्पादन में अपना अच्छा योगदान दे सकती है।

प्रस्तावना

भारत में नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी कार्यप्रणाली अपनायी गयी है कि मध्यम एवं वृहद् उद्योगों में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की इकाईयाँ साथ–साथ चलती रहें। कुछ विशेष क्षेत्रों में तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ स्थापित की गयी, लेकिन लघु व अत्यन्त लघु क्षेत्रों तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों को केवल निजी क्षेत्र के लिये आरक्षित किया गया ताकि ज्यादा संख्या में इकाईयाँ स्थापित हों, कुल उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार प्रदान करने में इस क्षेत्र द्वारा मुख्य भूमिका निभायी गयी है। इन नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न तरह की इकाईयों की प्रगति के लिए निर्णय लेते रहे हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों के उद्योगों के लिए जैसे–हिल एरिया के उद्योगों, समुद्री किनारे के उद्योगों या अन्य विषम परिस्थितियों के उद्योगों के विकास के लिए अलग से परिवर्तनशील नीतियाँ अपनायी गयी हैं ताकि सभी परिस्थितियों में उद्योगों का सर्वतोन्मुखी विकास सम्भव हो सके। किसी भी देश को तब तक औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं माना जाता जब तक कि उस देश में उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय वितरण न हो, क्योंकि संतुलित क्षेत्रीय वितरण के माध्यम से देश में उपलब्ध क्षमताओं का कुशल उपयोग हो जाता है तथा देश का कोई भी क्षेत्र इसके लाभों से वंचित नहीं रह पाता है। इस प्रकार के विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक अलग से क्षेत्रीय योजना होनी चाहिये जिससे कि स्थानीय बेरोजगारी के समाधान का मूल खोजा जा सके।

आर्थिक विकास

आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, भारत में आर्थिक विकास को सफल व सकारात्मक बनाने के लिये आर्थिक नियोजन को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के माडलों पर आधारित नीतियों को अपनाया गया है। आर्थिक विकास किसी एक देश द्वारा अपने समस्त उत्पादक साधनों का वास्तविक आय में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। जिससे किसी देश अथवा क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों को इस प्रकार प्रयोग करने लगते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं से प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है।

आर्थिक विकास की प्रकृति मूलतः प्रावैगिक है। यह एक ओर 'आर्थिक गति' की स्थितियों का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर दीर्घकाल में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करता है।

प्रो॰ रोस्टोव के अनुसार, प्रत्येक अर्थव्यवस्था पाँच प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। यह परम्परागत अवस्था से स्वयं स्फूर्त विकास द्वारा नियमित विकास की अवस्था को प्राप्त होती है, तत्पश्चात् परिपक्वता एवं अधिक उपभोग की अवस्था पर आती है।

प्रो॰ कोलिन क्लार्क के अनुसार, "आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को बताता है, जिससे बढ़ती हुई पूँजी का प्रयोग एक निश्चित सीमा तक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि लाता है, किन्तु वहाँ से पूँजी की आवश्यकता कम होती जाती है।"

प्रो॰ लेविस के अनुसार, "आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से है तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होना एक ओर तो उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है तथा दूसरी ओर मानव व्यवहार पर।"

आर्थिक नियोजन

मानव समाज के लिए आर्थिक नियोजन का विचार नया नहीं है। वह सदैव से ही मनुष्य के विवेकपूर्ण व्यवहार का आधार रहा है। आधुनिक युग तो आर्थिक नियोजन का युग कहलाता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक दिशा में नियोजन का सर्वाधिक महत्व है। आज विश्व अर्थव्यवस्था की धमनियों में अर्थ नहीं बल्कि नियोजन प्रवाहित हो रहा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी सर्वतोमुखी सफलता के लिए विभिन्न चरणों में योजनाबद्ध कार्यक्रम अपनाता है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक नियोजन को अपनाता है।

प्रो॰ हैरिस के अनुसार, "नियोजन से अभिप्राय आय तथा मूल्य के सन्दर्भ में नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के लिए साधनों का आंवटन मात्र है।"

श्रीमती बारबरा वूटन ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा दो विभिन्न दृष्टिकोणों से दी है–

प्रथम दृष्टिकोण–"सार्वजनिक अधिकारी द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का सचेत, विवेकपूर्ण तथा इच्छानुसार किया गया निर्वाचन तथा निर्धारण ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है।"

द्वितीय दृष्टिकोण–"आर्थिक नियोजन वह व्यवस्था है जिसमें विपीण संयन्त्र की कार्यविधि में इस दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाता है कि ऐसी व्यवस्था या क्रम उत्पन्न हो जाए जो विपणि संयन्त्र के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने पर विकसित होने वाले क्रम से पूर्णतया भिन्न हो।"

प्रो॰ एच॰ लेवी के अनुसार, "आर्थिक नियोजन से अभिप्राय, माँग और पूर्ति में, सापेक्षतः एक उत्तम सन्तुलन प्राप्त करना है। यह सन्तुलन उत्पादन अथवा वितरण अथवा दोनों के सन्दर्भ में एक चेतनापूर्ण, विवेकशील तथा एक पूर्व निर्धारित ढंग से प्राप्त किया जाता है न कि इसके विपरीत इस सन्तुलन को अदृश्य, स्वतः संचालित तथा अनियमित शक्तियों के हाथ में छोड़कर।"

आज प्रत्येक देश में यह प्रयास किया जा रहा है कि छोटे व्यवसाय एवं उद्योगों को अधिक से अधिक विकसित किया जाये, ताकि ये अपने आप में पूर्ण उद्योग का दर्जा प्राप्त कर सकें, आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो सके और बड़ी इकाईयों के पूरक उद्योगों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें सम्भवतः यही कारण है कि अपने देश में भी बड़ी इकाईयों के साथ–साथ छोटी इकाइयों की भी महत्ता समझी जा रही है और उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी व वित्तीय संस्थाओं को भी इस प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर लोगों को इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिल रही है, वही दूसरी ओर इकाइयों की स्थापना और इनके परिचालन में सहायता प्राप्त हो रही है। सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना की दिशा में उद्यमशीलता को यदि हम आज के विकास का मूल मंत्र मानते हैं, तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उद्यमशीलता के अभाव में विकास की किसी भी शाखा का अस्तित्व में आना सम्भव न होगा। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में विकास की कल्पना करना उद्यमशीलता के बिना व्यर्थ है। उद्यमशीलता के साथ–साथ साहस और अभिप्रेरण का भी अपना

महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साहस के माध्यम से ही कोई व्यक्ति सही दिशा में निर्देशित होता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर अपने लक्ष्य पर पहुँचने का प्रयास शुरू करता है।

दमोह जिला औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा जिला है। इसका मुख्य कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा लोगों में उद्यमिता का अभाव है। ग्रामीण जनसंख्या में लगतार वृद्धि होने कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन की क्षमता अनुपातिक रूप से कम होती है। वैसे भी कृषि कार्य में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। अत नगरी क्षेत्र की जनसंख्या के समान ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को भी औद्योगिक क्षेत्र में नये–नये आयामों को निर्मित और संचालित कराना होगा। भारत की केन्द्र सरकार तथा मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने दमोह जिले के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त उद्योगो के स्थपना हेतु रियायती दर पर भूमि बिजली किस्तों पर मशीनों के क्रय करने की सुविधा प्रदान की है। पूंजी के लिये बैंकों तथा औद्योगिक वित्तीय संस्थओं के माध्यम से ऋण प्रदान करने की सुविधा भर प्रदान करने का प्रावधान है।

दमोह जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा– (1) प्रधानमंत्री रोजगार योजना, (2) मुख्य मंत्री पिछड़ वर्ग स्वरोजगार योजना, (3) दीनदयाल रोजगार योजना, (4) रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अजनजाति स्वरोजगार योजना संचालित की जाती है। जिनका मुख्य उद्देश्य जिले में बेराजगार, पिछड़े वर्ग एवं महिलओं को स्वरोजगार के रूप में सेवा उद्योग, व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है।

संक्षेप में, दमोह जिले के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु वित्त की अधिकारिक उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दमोह जिला उद्योग केन्द्र नये उद्यम की जानकारी व स्थपना हेतु समुचित मार्गदर्शन करता है, लेकिन उद्यम के प्रारंभ से लेकर अंतिम उत्पादन और बाजार तथा विपणन के प्रवाह तक पग–पग पर पूंजी और कर्म–कौशल का कोई महत्व नही हैं। यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है।

उद्देश्य

- दमोह जनपद में आर्थिक विकास की स्थिति, रोस्टोव तथा रोडान के मॉडल का अध्ययन करना।
- कुटीर उद्योगों से रोजगार के अवसर पैदा होने पर गरीबी विषमता में हुए सकारात्मक सुधारों का अध्ययन करना।
- सशक्त व मजबूत आधारभूत संरचना से, जनपद में बैंकिग, बीमा व शिक्षा के क्षेत्र में हुये सकारात्मक परिणामों का अध्ययन करना।
- दमोह जनपद के विकास में सरकारी नीतियों के योगदान का अध्ययन करना।
- कृषि उत्पादकता में विषमता के कारण दमोह जनपद के औद्योगिक विकास की स्थिति का अध्ययन करना।
- आर्थिक सुधारों के बाद दमोह जनपद में गुणात्मक मानव संसाधन के विकास का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

- आर्थिक विकास एवं आर्थिक नियोजन एक–दूसरे के पूरक हैं।
- दमोह जनपद में सातवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व कुटीर उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ।
- आर्थिक सुधारों के बाद जनपद में औद्योगिक विकास काफी तेजी से हुआ।
- दमोह जनपद के विकास में कुटीर उद्योगों का बहुत योगदान है।
- दमोह जनपद में आर्थिक सुधारों के बाद आधारभूत ढाँचे की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
- आर्थिक नियोजन ने कृषि क्षेत्र के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

- दमोह जनपद में आर्थिक सुधारों के बाद प्रति व्यक्ति आय, रोजगार व गरीबी उन्मूलन की स्थिति में सुधार हुआ है।
- दमोह जनपद के विकास में सरकारी नीतियाँ अधिक कारगर साबित नहीं हुई हैं।

शोध पद्धतिः

प्रस्तुत अध्ययन प्रारम्भिक तथा द्वितीयक समंकों पर आधारित है। द्वितीयक समंक मुख्यतया जिला उद्योग की रिपोर्ट, समाचार पढ़ने, पत्रिकाओं, उद्योग संस्थानों (प्रकाशित तथा अप्रकाशित) इत्यादि से प्राप्त किये जायेंगे। प्राथमिक समंक विभिन्न क्षेत्रों से दैव–निर्देशन विधि द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। एक उचित प्रश्नावली तैयार करके प्राथमिक समंक एकत्रित किये जायेंगे। दमोह जनपद को हम एक समग्र मानेंगे। यह जनपद के विभिन्न ग्रामों व शहरों में से दैव–निर्देशन विधि द्वारा एक प्रतिनिधि निर्देश लिया जायेगा तथा इन निर्देशों को आवश्यकतानुसार वर्गीकृत करके वांछित परिणाम प्राप्त किये जायेंगे। पर्याप्त सूचनाओं के आधार पर समंक इकट्ठे करके सारणीयन एवं वर्गीकृत किया जायेगा, तत्पश्चात् विभिन्न सांख्यिकी विधियों एवं तकनीकियों की सहायता से समंकों का विश्लेषण करके निश्चित परिणाम प्राप्त किये जायेंगे।

सन्दर्भ सूची

होस्मर, एल0 एस0 – दि इन्टरप्रिन्योरियल फंक्शन प्रेन्टिस हॉल न्यू जर्सी, 1977

लघु उद्योग विकास विभाग भारत सरकार – ए हैण्डबुक ऑफ सरल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट, 1988

लघु उद्योग विकास विभाग भारत सरकार – ए हैण्डबुक फॉर एक्सटेन्सिव सर्विसेज

हसबैण्ड एण्ड डाकरे – इन्ट्रोडक्शन टु बिजनेस फाइनेन्स, 1987

हाबार्ड एण्ड उपटोन – मॉर्डन कॉरपोरेशन फाइनेन्स, 1987

डेनिस, राबर्टसन – कन्ट्रोल ऑन इण्डस्ट्री

मरे डी॰, ब्राइस – इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट

फ्लोटेन्स, पी0 एम0 – इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलॉजी ऑफ इण्डस्ट्री

मिल्टन, फ्रेण्डमैन – कैपिटेलिज्म एण्ड फ्रीडम

कनका, एस0एस0 – इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट इन कुमायूं, 1988

वी0 रामचन्द्र राव – दि इण्डस्ट्रियल सिकनेस एण्ड दि मॉनिटरिंग टूल, दि बैंकर, सितम्बर 1991

जी0 रामचन्द्रन – ग्रोथ ऑफ स्मॉल सेक्टर इकोनोमिक टाइम, अप्रैल 22, 1986

सी0वी0 कुप्युस्वामी – स्मॉल यूनिट्स माइल्स टू गो फाइनेन्शियल एक्सप्रेस